



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 31, 2005/कार्तिक 9, 1927

No. 285]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2005/KARTIKA 9, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2005

अंतिम जांच परिणाम

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय :— ईयू, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मिथाईलीन क्लोराइड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी (मध्यावधि समीक्षा)

सं० 15/28/2004-डीजीएडी:- 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

2(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने ईयू, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मिथाईलीन क्लोराइड के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 14 अगस्त, 2003 को अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना सं. 17/1/2001-डीजीएडी अधिसूचित की थी।

(ii) इस कार्यवाही में मूल जांच 19 अगस्त, 2002 को शुरू की गयी थी। प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 24 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना सं० 17/1/2001-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 14 अगस्त, 2002 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं० 17/1/2001-डीजीएडी निकाला। संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 27.03.2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 49/2003 द्वारा अंतिम शुल्क लगाया गया था।

ख. प्रक्रिया

3(i) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) और इसके अंतर्गत निर्मित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाए रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है।

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने के लिए इनिओस क्लोर समेत निर्यातकों की ओर से यूरोपीय आयोग से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त आवेदक द्वारा प्रदत्त सकारात्मक सूचना के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना कि निर्यातक द्वारा प्राधिकारी की जानकारी में लायी गयी परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उपयुक्त होगा। तदनुसार, प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत से संबंधित एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 28.01.2005 को प्रकाशित हुई थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लगातार लागू रखना चाहिए और क्या शुल्क को समाप्त करने अथवा उसे परिवर्तित करने अथवा दोनों स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी।

(iii) इन अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने के पश्चात् प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथा संशोधित) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार ईयू, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मिथाईल क्लोराइड पर पाटनरोधी शुल्क को लगाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए 28/1/2005 की अधिसूचना सं० 15/28/2004-डीजीएडी द्वारा वर्तमान जांचों की शुरुआत की थी। इस समीक्षा में 14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० 17/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

(iv) समीक्षा की शुरुआत करने के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों के ज्ञात सभी निर्यातकों/उत्पादकों को जांच संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजीं।

(v) मूल जांच में उपलब्ध पतों के अनुसार नियमानुसार संगत सूचना मंगाने के लिए भारत में घरेलू उद्योग को नोटिस जारी किए गए।

(vi) नई दिल्ली में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें।

(vii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए मूल जांच में उपलब्ध पतों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियाँ भेजी गयीं।

(viii) यह जांच 01.04.2003 से 31.3.2004 (जांच अवधि) तक की अवधि (12 महीने) के लिए की गयी थी। तथापि, क्षति का विश्लेषण अप्रैल 2000-मार्च, 2001, अप्रैल, 2001-मार्च, 2002 और अप्रैल, 2002-मार्च, 2003 एवं जांच अवधि के लिए किया गया था।

(ix) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था।

(x) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियाँ व्यापक परिचालन हेतु फिक्की, सीआईआई और एसोचैम को भी भेजी गयी थीं ।

(xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखे ।

(xii) संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक मै0 गुजरात अल्काली केमिकल्स लि0 और मूल याचिकाकर्ता ने इस समीक्षा का विरोध करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया है ।

(xiii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने के लिए सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर इष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत की गणना करने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का संभव सीमा तक सत्यापन किया ।

(xiv) प्राधिकारी ने 16.06.2005 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए किया जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, यूरोपीय यूनियन की संबद्ध वस्तु के आवेदक, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया । सार्वजनिक सुनवाई में शामिल हितबद्ध पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित उत्तरों पर प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में विचार किया गया है ।

(xv) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में और बाद में सार्वजनिक सुनवाई में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों पर नियमानुसार उस सीमा तक संगत पैराग्राफों में विचार किया गया है जिस सीमा तक ये संगत हैं और मामले पर प्रभाव रखते हैं । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों की जांच की गयी है, उन पर विचार किया गया है और जहां उचित हो, वहां संगत पैराग्राफों पर कार्रवाई की गयी है ।

(xvi) उपर्युक्त नियम 16 के अनुसार, इन जांच परिणामों में विचारित आवश्यक तथ्यों/आधारों का खुलासा दिनांक 13.9.2005 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में विधिवत रूप से विचार किया गया है ।

*** यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माने जाने का द्योतक है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जाँच में शामिल उत्पाद और वर्तमान समीक्षा आईटीएसएच वर्गीकरण और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में 29031200 शीर्ष के अंतर्गत आने वाला मिथाइलीन क्लोराइड है । तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है । यह परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा जांच है । इस जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद है । किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के मुद्दे अथवा समान वस्तु के बारे में कोई तर्क नहीं

दिया गया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्माण किया जा रहा उत्पाद और संबद्ध देशों द्वारा निर्यातित उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं हैं।

घ. घरेलू उद्योग

5. मूल जांच में पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स गुजरात अल्काली एण्ड कैमिकल्स लि० द्वारा दायर किया गया था। आवेदक भारत में संबद्ध माल का प्रमुख उत्पादक था और उसके पास पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त आधार था। इस मध्यावधि समीक्षा में मैसर्स गुजरात अल्काली एवं कैमिकल्स लि० सभी संगत सूचना प्रदान कर रहा है और समर्थन मैसर्स कैमप्लास्ट सनमार और मैसर्स एसआरएफ लि० द्वारा किया जा रहा है। मैसर्स कैमप्लास्ट सनमार लि० ने लागत निर्धारण एवं क्षति संबंधी सूचना भी प्रस्तुत की थी। तथापि, जांच में यह सूचना गलत एवं अविश्वसनीय पायी गयी थी। इसलिए कम्पनी द्वारा प्रदत्त लागत एवं क्षति संबंधी सूचना पर इस जांच में विश्वास नहीं किया गया है। अतः मैसर्स गुजरात अल्काली एवं कैमिकल्स लि० पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग बनता है।

ड. समीक्षा की शुरुआत और दिए गए तर्क

ड.1 आवेदकों के विचार

6. आवेदकों के विचारों को संक्षेप में नीचे दिया गया है

आवेदक का दावा है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की दशा में पर्याप्त रूप से परिवर्तन हुआ है जिससे लागू पाटनरोधी उपायों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। यह दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2002-03 में गुजरात अल्कालीज एवं कैमिकल्स लि० का मिथाइल क्लोराइड का उत्पादन 25481 मी. टन था। आवेदक का दावा है कि यद्यपि उत्पादन वर्ष 2002-03 से 2003-04 में केवल 1% तक बढ़ा है किन्तु बिक्रियां इसी अवधि में 616 मिलियन रूपए से 702 मिलियन बढ़ने से 14% तक वृद्धि हुई है। आवेदक का यह भी दावा है कि मिथाइलीन क्लोराइड की स्थापित क्षमता 2002 से 23760 मी. टन रह गयी थी और उपयोगिता 100% से अधिक रहीं है क्योंकि उत्पादन का स्तर वर्ष 2002-03 के 25481 मी. टन से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 25784 मी. टन तक पहुँच गया था। अतः घरेलू उद्योग अधिकतम उत्पादन कर रहा है और उसे कम क्षमता उपयोग का नुकसान नहीं है। आवेदक का यह भी दावा है कि भारत में मिथाइलीन क्लोराइड की मांग लगभग 57000 मी. टन/वर्ष की है। तथापि, भारत में घरेलू विनिर्माताओं (गुजरात अल्कालीज लि० चेमप्लास्ट सनमार और एसआरएफ लि०) का वर्तमान वार्षिक उत्पादन का स्तर लगभग 30,000 मी. टन है। घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत में प्रयोक्ता उद्योग वर्तमान में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के बावजूद मिथाइल क्लोराइड का आयात करने के लिए वचनबद्ध है। घरेलू उत्पादकों ने बढ़ती घरेलू खपत के बावजूद अपनी क्षमता नहीं बढ़ायी है जिससे यह संकेत मिलता है कि कथित पाटन से भिन्न अन्य ऐसे तत्व हैं जो अपने उत्पादन का विस्तार करने से रोक रहे हैं। आवेदक का यह भी कहना है कि जांच अवधि के पश्चात् बाजार में कीमतें दोगुनी हो गयी हैं। पाटनरोधी शुल्क लागू करते समय कीमतें 270-350 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की सीमा में थीं। ये कीमतें अब बढ़कर 650 अमरीकी डालर/मी. टन हो गयी हैं और इस स्तर पर पर्याप्त समयावधि तक रही है। आवेदक दावा करते हैं कि इन ऊँची कीमतों से यह संकेत मिलेगा कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है। यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2004 के दौरान भारत के लिए मिथाइल क्लोराइड की औसत निर्यात

कीमत पैक किए गए उत्पाद के लिए 655 डालर/मी. टन और बल्क उत्पाद के लिए 611 डालर/मी. टन थी ।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग के विचार संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :-

- i) आवेदक उस विचाराधीन उत्पाद के बारे में स्पष्ट नहीं है जिसकी समीक्षा की जा रही है । अग्रेषण-पत्र जो यूरोपीय आयोग का एक पत्र है, में शीर्ष विषय के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के रूप में मिथाइल क्लोराइड के बारे में उल्लेख है जबकि पत्र में कोलीन क्लोराइड के आयातों पर शुल्क की समीक्षा का उल्लेख किया गया है ।
- ii) आवेदन उस आवेदक के बारे में अस्पष्ट है जिसने पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा की मांग की है ।
- iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत इस सकारात्मक सूचना के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी की इस प्रकार की संतुष्टि जांच की शुरुआत करने से पूर्व होनी चाहिए न कि जांच की प्रक्रिया के दौरान । वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा ऐसी कोई सकारात्मक सूचना प्रदान नहीं की गयी है जिससे पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने की जरूरत को औचित्यपूर्ण कहा जा सके ।
- iv) आवेदक मैसर्स इनिओस क्लोर ने न तो मूल जांच के दौरान और न ही वर्तमान जांच के दौरान सहयोग किया । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भी मैसर्स इनिओस क्लोर ने कोई अनुरोध नहीं किया ।
- v) उस हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर समीक्षा की जा सकती है जिसने ऐसी परिस्थितियां प्रदान की है जिसमें पहले पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गयी थी, जो परिवर्तित हो गयी है और शुल्क को निरस्त करने, उसे बढ़ाने अथवा घटाने की आवश्यकता है । तथापि, वर्तमान मामले में, कथित परिस्थितियां "परिवर्तित परिस्थितियां" नहीं है जिससे मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता पड़ती हो । यूरोपीय आयोग अथवा एक यूरोपीय उत्पादक द्वारा दायर आवेदन में सकारात्मक साक्ष्य की कमी है जिसमें परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख है । आवेदक का यह आधार नहीं है कि उत्पाद का भारतीय बाजार में अब पाटन नहीं किया जा रहा है । यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर से शुल्क लगाने के पश्चात भी पाटित कीमतों पर आयात जारी हैं ।
- vi) आवेदक का दावा " कोई वास्तविक क्षति नहीं " तक ही सीमित है और इसमें "घरेलू उद्योग को किसी क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना " शामिल नहीं है । अतः दावा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने अथवा उसे समाप्त करने की कानूनी अपेक्षाओं के आलोक में अपर्याप्त है ।
- vii) आवेदक का दावा वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल क्लोराइड पर आधारित नहीं है और आवेदक ने असंगत और अनुपयोगी सूचना पर विश्वास किया है ।
- viii) उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में मामूली सुधार उत्पादन में सुधार लाने के भारतीय उत्पादकों के सतत प्रयासों का परिणाम है । इससे पाटनरोधी शुल्क को निरस्त करने का उचित आधार माने जाने की कल्पना नहीं की जा सकती है ।
- (ix) माँग की पूर्ति में घरेलू उद्योग की असमर्थता पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पूर्व अपेक्षित नहीं थी । यह पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण के लिए मापदंड नहीं बन सकता है ।
- (x) आवेदक ने तर्क दिया है कि शुल्क के लागू होने से निर्यात कीमतों में वृद्धि हुई है । तथापि, यह देखा जाना चाहिए कि सम्पूर्ण विश्व में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है । क्लोरीन जो कि मुख्य कच्चा माल है, की कीमतों में पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के पश्चात अत्यधिक वृद्धि हुई है और कीमतों में वृद्धि जैसा कि निर्यातकों ने उल्लेख किया है उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई है ।

(xi) सिंगापुर एवं दक्षिण अफ्रीका के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत के किसी आयातक द्वारा सिंगापुर एवं दक्षिण अफ्रीका से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पर पुनर्विचार के लिए रिकार्ड में कोई आवेदन नहीं है।

(xii) यह विधि का स्थापित सिद्धान्त कि जो दावा करता है वही उसे साबित करता है। इसलिए, यह स्थापित करने का दायित्व कि कथित आहरण की इच्छुक पार्टी पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की आवश्यकता है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान दिया है और उनका विचार है कि यूरोपीय आयोग ने मै. इनोज क्लोर ऑफ यूरोपियन यूनियन सहित निर्यातकों की ओर से अनुरोध किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अनुरोध राजनयिक माध्यम के जरिए भेजा गया था। पाटनरोधी करार एवं पाटनरोधी नियमों के अनुसार इस मामले में यूरोपीय आयोग एवं मै. इनोज क्लोर दोनों हितबद्ध पक्षकार हैं और दोनों को आवेदन दाखिल करने का अधिकार है। इस मामले में यूरोपीय आयोग को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण निर्यातक की ओर से समीक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने का अधिकार है।

9. घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क कि उत्पाद स्पष्ट नहीं है जबकि अग्रेषित पत्र के पाठ में 'कोलिन क्लोराइड' का उल्लेख है। प्राधिकारी का विचार है कि विचाराधीन उत्पाद मेथाइलेन क्लोराइड है जैसा कि शीर्षक विषय के अंतर्गत पत्र पर उल्लिखित है। पत्र में मेथाइलेन क्लोराइड से संबंधित परिवर्तित परिस्थितियों के विषय में बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया है। पत्र में कोलिन क्लोराइड के विषय में भी उल्लेख है, तथापि मेथाइलेन क्लोराइड से सम्बन्धित परिवर्तित परिस्थितियों पर सम्पूर्ण उल्लेख को नकारा नहीं जा सकता है।

10. निर्यातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा सहयोग की कमी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 एवं पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत दर्शाया गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में पहले से ही प्रचलित नियमों का पालन किया है।

11. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी की 'संतुष्टि' जांच शुरुआत से पहले आवश्यक है न कि जांच करने के दौरान। इस संबंध में उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11(2) की ओर दिलाया है।

12. प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11(2) एवं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(5) तथा संगत पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखा है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क के लगातार जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वे इस तथ्य से संतुष्ट होते हैं कि ऐसे शुल्क का लगातार लागू रहना न्यायसंगत नहीं है तो वे केन्द्र सरकार से इसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे और करार के अनुच्छेद 11.2 में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकारी जहाँ भी आवश्यकता हो अपनी निजी पहल पर शुल्क के सतत जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे अथवा बशर्ते कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा जो कि समीक्षा की आवश्यकता को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना

प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के पश्चात् एक उपयुक्त समयावधि व्यतीत हो चुकी हो। हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी से यह अनुरोध करने का अधिकार है कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लगातार लागू रहना चाहिए और क्या शुल्क को समाप्त करने अथवा उसे परिवर्तित करने के बाद क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने अथवा दोनों की संभावना रहेगी, इस पैराग्राफ के अंतर्गत यदि समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता नहीं है तो इसे तुरन्त समाप्त किया जाए।

13. प्राधिकारी ने तर्क की जांच की और उनका विचार है कि नियम 23 में 'संतुष्टि' की शर्त का तात्पर्य उपयुक्त जांच करने के पश्चात् शुल्क को लगातार लागू रहने की आवश्यकता से प्राधिकारी का संतुष्टि से है न कि समीक्षा की शुरुआत से। समीक्षा की शुरुआत के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वह प्राधिकारी के पास सकारात्मक सूचना है जिस पर निर्भर करते हुए प्राधिकारी यह निश्चित करते हैं कि क्या शुल्क के लगातार लागू रहने की आवश्यकता की जांच की समीक्षा की जरूरत है। वर्तमान मामले में आवेदक ने अपने समीक्षा आवेदन में प्राधिकारी के समक्ष सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की थी और यह समीक्षा प्रस्तुत इस सकारात्मक सूचना के आधार पर शुरू की गयी थी। सकारात्मक सूचना का तात्पर्य ऐसी किसी सूचना से होता है जिसके आधार पर प्राधिकारी समुचित कार्रवाई कर सकता है। तथापि, प्राधिकारी से आरंभिक स्तर पर यथोचित साक्ष्य के साथ सूचना की जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जैसा कि जांच की कार्रवाई के दौरान किया जाता है। विभिन्न पार्टियों के दावों और प्रतिदावों की पुष्टि हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करना जांच का विषय है और इसे जांच की कार्रवाई के दौरान समीक्षा का अनुरोध करने वाली पार्टी सहित पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना होता है। तथापि, समीक्षा का परिणाम समीक्षा की विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि यह समीक्षा प्राधिकारी के पास उपलब्ध सकारात्मक सूचना के आधार पर सही ढंग से शुरू की गयी है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि लागू शुल्क की समीक्षा अपेक्षित थी।

14. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इस समय पूर्व स्तर पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की जरूरत को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्ता पर होता है। घरेलू उद्योग से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह पाटनरोधी शुल्क को निरन्तर लगाए जाने की जरूरत को प्रमाणित करे और घरेलू उद्योग से इस बात की पुष्टि की अपेक्षा नहीं की जाती है कि पाटनरोधी शुल्क के निरसन के परिणामस्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जरूरी है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 11(1), 11(2) एवं धारा 23 में निहित उपबंध को ध्यान में रखा गया है। इन उपबंधों के अनुसार इस आशय की प्राप्त सूचना के आधार पर कि पाटनरोधी शुल्क को निरन्तर लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, संतुष्टि होने के बाद प्राधिकारी ऐसे शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करेंगे। प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस उपबंध के तहत प्राधिकारी को प्राप्त सूचना के आधार पर उसकी संतुष्टि का भार आ जाता है। प्राधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी संतुष्टि हेतु सामग्री की जांच करे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को निरन्तर लगाए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसका तात्पर्य पाटनरोधी शुल्क को निरन्तर लगाए जाने के लिए सूचना के अभाव से भी होता है। कोई भी हितबद्ध पार्टी इस आधार पर बचाव नहीं कर सकती कि दूसरी हितबद्ध पार्टी सहयोग नहीं कर रही है और इसलिए प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। न तो पाटनरोधी करार और न ही पाटनरोधी नियमावली में असहयोगी पार्टियों के प्रति ऐसा प्रतिकूल

दृष्टिकोण अपनाने का अधिदेश नहीं है। असहयोगी हितबद्ध पार्टियों से निपटने के लिए प्राधिकारी से उक्त करार और नियमावली के उपबंध के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करने की अपेक्षा की जाती है। अतः प्राधिकारी हितबद्ध पार्टियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना समेत उसके पास किसी स्रोत से उपलब्ध सूचना पर विश्वास कर रहे हैं।

15. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति के अभाव के बारे में आवेदक के दावे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अन्य तर्कों को भी ध्यान में रखते हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करते समय इन तर्कों को ध्यान में रखा गया है।

च. पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए प्रणाली :

पाटन निर्धारण: सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1. यूरोपीय संघ

च.1.1. सामान्य मूल्य

16. प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजीं। ईयू के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित ढंग एवं प्रारूप में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया है।

17. करार के अनुच्छेद 6.8 में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालते हैं तो वे उपलब्ध सकारात्मक अथवा नकारात्मक तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक और अन्तिम निर्धारण कर सकते हैं। करार के परिशिष्ट II में आगे यह प्रावधान है कि इस तरह के निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किए जा सकते हैं क्योंकि ईयू के किसी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना दाखिल नहीं की है इसलिए सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इसलिए ईयू के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए खुले माल के लिए ****अम. डालर/मी.टन एवं पैक किए गए माल के लिए सामान्य मूल्य *** अम. डालर/मी.टन सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

च 1.2 निर्यात कीमत

18. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार ईयू ने जांच अवधि के दौरान 3012 मी. टन का निर्यात किया है। खुले एवं पैक किए माल के आंकड़ों का पृथक करने के पश्चात माल की कारखाना द्वार कीमत को निकालने के लिए अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़ा एवं समुद्री बीमे के कारण समायोजन किया गया है। ईयू के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए खुली सामग्री के लिए कारखाना द्वार कीमत का निर्धारण *** अम. डालर/मी.टन एवं पैक किए गए माल के लिए *** अम. डालर/मी.टन किया गया है।

च.2. सिंगापुर**च.2.1. सामान्य मूल्य**

19. प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजीं। सिंगापुर के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित ढंग एवं प्रारूप में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया है। किसी और सूचना की अनुपस्थिति में वर्तमान पाटन की सीमा तक पहुँचने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना को सामान्य मूल्य का आधार बनाया है। करार के अनुच्छेद 6.8 में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालते हैं तो वे उपलब्ध सकारात्मक अथवा नकारात्मक तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक और अन्तिम निर्धारण कर सकते हैं। करार के परिशिष्ट II में आगे यह प्रावधान है कि इस तरह के निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किए जा सकते हैं क्योंकि ईयू के किसी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना दाखिल नहीं की है इसलिए सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। सिंगापुर के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए *** अम. डालर/मी. टन सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

च.2.2. निर्यात कीमत

20. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर ने जांच अवधि के दौरान 44 मी. टन मिथाइलेन क्लोराइड का निर्यात किया गया है। खुले एवं पैक किए गए माल के आंकड़ों को पृथक करने के पश्चात माल की कारखाना द्वार कीमतों को निकालने के लिए अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़ा एवं समुद्री बीमे के कारण समायोजन किया गया है। सिंगापुर के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए कारखाना द्वार कीमत का निर्धारण *** अम. डालर/मी. टन किया गया है।

च.3. दक्षिण अफ्रीका

21. डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने मिथाइलेन क्लोराइड का कोई निर्यात नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी निर्यात कीमत का परिकलन नहीं कर सकते हैं।

च.4. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य एवं ऊपर निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया है :

संबद्ध देश	सामान्य मूल्य (डालर/मी.टन)		निर्यात मूल्य (डालर/मी.टन)		डम्पिंग मार्जिन (%)	
	खुला	पैक किया हुआ	खुला	पैक किया हुआ	खुला	पैक किया हुआ
ई यू	***	***	***	***	-5	-9
सिंगापुर		***		***		83

छ. क्षति निर्धारण एवं कारणात्मक संबंध की जांच के लिए प्रणाली

छ 1. क्षति निर्धारण एवं क्षति का जारी रहना

छ1.1 आवेदक के विचार

23. आवेदक ने आवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन में सुधार किया है और उसे कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। आवेदक का दावा है कि यद्यपि 2002-03 से 2003-04 में उत्पादन में वृद्धि केवल 1% हुई है किन्तु उसी अवधि में 616 मिलियन रु. से 702 मिलियन रु. की बिक्री होने से 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आवेदक का आगे दावा है कि मेथाइलेन क्लोराइड के लिए स्थापित क्षमता 2002 से 23760 मी. टन रहीं हैं और उपयोग 100% से अधिक रहा है जैसाकि उत्पादन स्तर 2002-03 में 25481 मी. टन एवं 2003-04 में 25784 मी. टन पर पहुँच गया था। इसलिए घरेलू उद्योग अधिकाधिक उत्पादन का रहा है और क्षमता के उपयोग की कमी से ग्रस्त नहीं है। शुल्क लगाए जाने के समय कीमतें 270-350 अम. डालर/मी.टन की सीमा में थीं, अब इन कीमतों में 650 अम. डालर/मी.टन की वृद्धि हो गयी है और एक विचारणीय समयावधि से इसी स्तर पर बनी हुई हैं। आवेदक का दावा है कि ये उच्च कीमतें यह संकेत करती हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है। यह सूचित किया गया है कि भारत के लिए मेथाइलेन क्लोराइड की निर्यात कीमत 2004 के दौरान पैक किए हुए उत्पाद के लिए 655 डालर/मी.टन और थोक उत्पाद के लिए 611 डालर/मी.टन थी।

छ.1.2 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग के विचारों का सार निम्नानुसार है :-

घरेलू उद्योग अपने उत्पादन को ईष्टतम बनाने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से घरेलू उद्योग को उत्पादन मात्रा में सुधार करने में आश्चर्यजनक रूप से सहायता मिली है। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि नहीं की है, जबकि इस उत्पाद में क्षमता समायोजन थोड़े समय के लिए व्यवहार्य नहीं है, घरेलू उद्योग ने उत्पादन मात्रा में अत्यधिक वृद्धि की है। एक बार इसने अनुचित कीमत वाले पाटित आयातों से बचाव किया है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में कमी नहीं आयी है बल्कि सुधार प्रदर्शित हुआ है। लाभों के निष्पादन में सुधार पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण निवेशों पर नकदी प्रवाह एवं लाभ प्राप्त हुआ है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन उत्पाद के बाजार में पाटन के कारण इन मापदंडों के अनुसार प्रतिकूल था।

25. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में परिवर्तन घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का परिणाम है न कि उत्पाद-वार निष्पादन का। घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में घरेलू उद्योग के समग्र कार्पोरेट निष्पादन के रूप में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग में मजदूरी में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि घरेलू उद्योग की वार्षिक वेतन वृद्धि, कर्मचारियों के देना अनिवार्य है, के कारण हुई है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। यद्यपि एक ओर घरेलू उद्योग रोजगार के स्तर को घटाने में समर्थ रहा है तथापि, दूसरी ओर वह अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि करने में भी सक्षम रहा है।

छ.1.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए क्षति संबंधी मानदंडों के विश्लेषण का प्रस्ताव करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को ऐसे पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति होना जारी है।

घ.2. आयात की मात्रा और आयात कीमतें

27. क्षति विश्लेषण अवधि के लिए डीजीसीआईएण्डएस आंकड़े यह दर्शाते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों समेत अनेक स्रोतों से आयात हुए थे। तदनुसार डीजीसीआईएण्डएस द्वारा यथा प्रदर्शित आयात निम्नानुसार हैं :

विभिन्न देशों से आयात		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जांच अवधि)
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	3225.00	8199.00	2697.74	3056.00
यूरोपीय संघ	मी. टन	3224.00	6178.00	2692.00	3012.00
सिंगापुर	मी. टन	1.00	1501.00	5.00	44.00
दक्षिण अफ्रीका	मी. टन	0.00	520.00	0.74	0.00
अन्य देश	मी. टन	630.00	649.00	3258.26	10190.00
कुल आयात	मी. टन	3855.00	8848.00	5956.00	13246.00
आयातों का बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	83.66	92.67	45.29	23.07
यूरोपीय संघ	%	83.63	69.82	45.20	22.74
सिंगापुर	%	0.03	16.96	0.08	0.33
दक्षिण अफ्रीका	%	0.00	5.88	0.01	0.00
अन्य देश	%	16.34	7.33	54.71	76.93

28. डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से 3012 मी. टन के आयात हुए हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यूरोस्टेट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जनवरी-दिसम्बर, 2004 के दौरान 10200 मी. टन के काफी अधिक आयात हुए हैं। घरेलू उद्योग का मानना है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात या तो घरेलू उद्योग द्वारा बताए नहीं गए हैं या फिर इनकी किसी अन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत निकासी की गई हो तथा इसमें पाटनरोधी शुल्क के प्रवचन की भी संभावना है।

29. प्राधिकारी ने इस तथ्य को नोट किया है कि यूरोस्टेट आंकड़ों में यूरोपीय संघ से भारत को काफी मात्रा में निर्यात दर्शाए गए हैं; तथापि उन्होंने यह भी नोट किया है कि ये आंकड़े कैलेण्डर वर्ष की जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए हैं जबकि जांच अवधि वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल, 03 से मार्च, 04 के लिए है।

30. आईबीआईएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में आयातों की वही मात्रा दर्शाई गई है जैसी कि डीजीसीआईएण्डएस द्वारा दर्ज की गयी है। आईबीआईएस द्वारा प्रकाशित मूल्यवार आंकड़े भी डीजीसीआईएण्डएस से समानता दर्शाते हैं। यद्यपि उत्पादों के प्रति इकाई मूल्य में थोड़ा अंतर है, तथापि डीजीसीआईएण्डएस, आईबीआईएस और यूरोस्टेट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में मात्रा के संबंध में भारी अंतर है। अतः प्राधिकारी ने इस तथ्य को नोट किया है कि आयातों की मात्रा डीजीसीआईएण्डएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से अधिक हो सकती है।

31. डीजीसीआईएण्डएस और आईबीआईएस के आंकड़ों में खुले और पैक किए गए आयातों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आयातों के आंकड़े अलग करने के लिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा अपनायी गयी पद्धति से सहमत है। इस पद्धति से, केवल कांडला और मुम्बई पत्तनों के आंकड़ों का

प्रयोग किया गया है क्योंकि इन्हीं दोनों पत्तनों पर खुले आयातों के प्रहस्तन की सुविधा है। इसके अलावा केवल आयातों की उच्च मात्रा को खुली श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि खुले उत्पाद आम तौर पर कम मात्रा में आयात नहीं किए जाते हैं।

32. आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुल आयातों में संबद्ध देशों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है क्योंकि इनमें आधार वर्ष के दौरान लगभग 84% की तुलना में जांच अवधि के दौरान 23% की कमी हुई है। दक्षिण अफ्रीका से, जांच अवधि के दौरान आयात शून्य है। सिंगापुर से आयात जांच अवधि के दौरान 0.33% रहे हैं जबकि यूरोपीय संघ से जांच अवधि के दौरान आयातों का हिस्सा लगभग 23% बनता है। आयात आंकड़ों से अन्य देशों से आयात में भी काफी वृद्धि प्रदर्शित होती है। यह आधार वर्ष में 16% की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़कर 77% हो गया है।

33. प्रकटन के बाद के अपने अनुरोध में घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत की गणना के लिए कांडला पत्तन के आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए था। इस संबंध में, प्राधिकारी ने यह देखा है कि घरेलू उद्योग ने अपने मूल अनुरोध में निर्यात कीमत की गणना के लिए आईबीआईएस के आंकड़ों का प्रयोग किया है। इसके बाद के अनुरोधों में उन्होंने डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों का प्रयोग किया है और कांडला और मुम्बई पत्तनों पर किए गए आयात सौदों को अलग-अलग किया है और निर्यात कीमतों की गणना की है, तथापि, निर्यात कीमत की गणना करते समय पैकड सामग्री के अंतर्गत कतिपय उच्च मात्रा वाले सौदों पर विचार किया गया था। प्राधिकारी ने उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग किया है जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा अलग किया गया है तथापि उच्च मात्रा वाले सौदों पर खुली सामग्री के रूप में विचार किया गया है और तदनुसार निर्यात कीमत की गणना की गयी है। घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि निर्यात कीमत की गणना के लिए केवल कांडला पत्तन के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना अव्यवहार्य है क्योंकि कांडला और मुम्बई पत्तन दोनों में खुली सामग्री के प्रहस्तन की सुविधा है, इसलिए निर्यात कीमतों की गणना हेतु दोनों पत्तनों के आयात आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

छ.3. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

34. घरेलू उद्योग के निष्पादन की उसकी क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग की दृष्टि से और इन प्रतिमानों पर पाटित आयातों के प्रभाव, यदि कोई हों, की भी जांच की गई है। घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह आधार वर्ष 2000-01 में और जांच अवधि के दौरान समान रही है। यद्यपि क्षमता में जांच अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथापि इससे क्षमता उपयोग में सुधार प्रदर्शित होता है। यह आधार वर्ष में ही अपनी 100% से अधिक क्षमता पर कार्य कर रहा था और तब भी इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 3% की और वृद्धि हुई है। इसी प्रकार उत्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 3% की वृद्धि हुई है।

क्षमता उपयोग		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जांच अवधि)
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	100.00	100.00	100.00
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	93.89	96.33	103.40
उत्पादन					
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	93.89	96.33	103.40

छ.4. मॉग और बाजार हिस्सा

35. कुल मॉग का अनुमान घरेलू बिक्रियों और अन्य देशों से आयातों की संयुक्त मात्रा तथा संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में आयातों के आधार पर लगाया गया है। जाँच अवधि के दौरान मॉग में आधार वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के मामले में मॉग में बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान 69% तक की भारी गिरावट आई है। तथापि, अन्य देशों के लिए इसमें 2000-01 में 100 स्तर से 1171 तक की जबरदस्त वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति रही है और इसमें आधार वर्ष से जाँच अवधि के दौरान 78 तक की गिरावट आई है। इसी प्रकार अन्य घरेलू उत्पादकों के हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान 83 तक की कमी हुई है। यह दर्शाता है कि वृद्धिशील बाजार में यद्यपि घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग में सुधार करने में सक्षम था और उसने बिक्रियों के मूल्य और मात्रा के रूप में सुधार किया होता लेकिन घरेलू उद्योग और भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई। संबद्ध देश से बाजार हिस्से में भी गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है, तथापि संबद्ध देशों से इतर देशों ने काफी बड़ा हिस्सा हासिल किया है और 2000-01 में 100 के आधार से बढ़कर 1171 हो गए हैं।

मॉग में		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
व्यापारिक मॉग	मी. टन	***	***	***	***
		100.00	115.81	108.83	138.14
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	3225.00	8199.00	2697.74	3056.00
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	254.23	83.65	94.76
अन्य देशों से आयात	मी. टन	630.00	649.00	3258.26	10190.00
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	103.02	517.18	1617.46
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	93.73	96.31	107.12
अन्य भारतीय उत्पाद की बिक्रियाँ	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.82	106.06	114.31
मॉग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	80.93	88.49	77.55
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	90.51	97.45	82.75
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	219.53	76.86	68.60
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	88.95	475.21	1170.88
कुल		100.00	100.00	100.00	100.00

छ.5. घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्तियाँ

36. बिक्री मात्रा में 2000-01 में 100 के स्तर की तुलना में जाँच अवधि के दौरान 7% तक की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में बिक्री मूल्य में 23% तक की वृद्धि हुई है जिससे बेहतर प्राप्तियाँ प्रदर्शित होती है।

37. जाँच अवधि के दौरान खुली सामग्री की बिक्री मात्रा में 1% की वृद्धि हुई है। तथापि इसी अवधि में बिक्री मूल्य में 22% की वृद्धि हुई है जिससे प्राप्तियों में काफी सुधार प्रदर्शित होता है। पैक की गई सामग्री की बिक्री मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान 26% की वृद्धि हुई है। तथापि इसी अवधि के दौरान बिक्री मूल्य में 36% की वृद्धि हुई है जिससे बेहतर वसूली प्रदर्शित होती है।

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
	मात्रा मूल्य	मात्रा मूल्य	मात्रा मूल्य	मात्रा मूल्य	मात्रा मूल्य
निम्न में वास्तविक और संभावित गिरावट	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख
बिक्रियाँ					
बिक्रियाँ (घरेलू)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	94	86
खुली बिक्रियाँ	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	90	80
पैकड बिक्रियाँ	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	106	100
निर्यात बिक्रियाँ	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	33	31

छ.6. कीमत कटौती

38. जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की तुलना पाटित आयातों के भारित औसत पहुँच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई थी। संबद्ध देशों से आयातों का पहुँच मूल्य जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों से कम था और इस प्रकार इससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती हो रही थी। जाँच अवधि के दौरान कटौती का मार्जिन निम्नलिखित परिधि के बीच था :-

कीमत कटौती	ईयू (खुली)	ईयू (पैकड)	सिंगापुर (पैकड)
निवल बिक्री प्राप्तियाँ	***	***	***
पहुँच मूल्य	***	***	***
कीमत कटौती	***	***	***
कीमत कटौती (%)	***	***	***
कीमत कटौती की सीमा	1-10%	1-7%	20-30%

छ.7. कम कीमत पर बिक्री

39. कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का महत्वपूर्ण संकेतक है; इस प्रकार प्राधिकारी क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा की गणना के लिए पहुँच मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। घरेलू उत्पादक के लिए क्षतिरहित कीमत का मूल्यांकन जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा अक्षमताओं को समाप्त करने के लिए क्षमता उपयोग को मानकीकृत किया गया है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारित औसत पहुँच मूल्य जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से कम है। जाँच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन निम्नांकित दायरे के बीच था :-

कम कीमत पर बिक्री	ईयू (खुली)	ईयू (पैकड)	सिंगापुर (पैकड)
क्षतिरहित कीमत	***	***	***
पहुँच मूल्य	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री की सीमा	5-15%	4-13%	25-35%

40. इसके अलावा, संबद्ध वस्तु का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम है और इस तरह से इससे घरेलू बिक्री कीमत में कटौती हो रही है।

अन्य क्षति सम्बन्धी मापदण्ड:

41. मात्रा तथा आयतों का मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा घरेलू उद्योग की बिक्री तथा साथ ही साथ पूर्ववर्ती खण्ड में विभिन्न क्षेत्रों के बाजार हिस्सों के साथ मांग के स्वरूप जैसे क्षति सम्बन्धी प्रमुख मापदण्डों की जाँच करने के पश्चात अन्य आर्थिक मापदण्डों, जिनसे घरेलू उद्योग की मौजूदा क्षति का पता चल सके, का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :

छ.8. लाभप्रदता

42. कंपनी के अभिलेख से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का विश्लेषण किया गया है :-

43. ब्याज को छोड़कर उत्पादन की लागत आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान खुले उत्पाद के मामले में 17% बढ़ी तथा बंद उत्पाद के लिए 15% बढ़ी। बिक्री कीमत में खुले उत्पाद के लिए 22% तथा बंद उत्पाद के लिए 8% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। लाभप्रदता में सुधार प्रदर्शित हुआ है तथा आधार वर्ष में 100 के खुले उत्पाद के घाटे के लिए सूचीबद्ध रूप में जो घनात्मक हो गया तथा सूचीबद्ध रूप में यह 96 हो गया। बंद उत्पाद के लिए इसमें गिरावट प्रदर्शित होती है तथा आधार वर्ष में 100 का लाभ जाँच अवधि से -2 के दौरान नकारात्मक हो गया। लाभ में सुधार प्रदर्शित हुआ है तथा आधार वर्ष के 100 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान यह बढ़कर 480 हो गया।

लाभ-घरेलू बिक्री		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
उत्पाद की लागत (खुला)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	82.89	125.00	109.28
उत्पादन की ब्याज रहित निवल लागत (खुला)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	130	117
उत्पादन की लागत (पैकड)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	122	102
उत्पादन की ब्याज रहित निवल लागत (पैकड)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	82	125	115
बिक्री कीमत (खुला)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	88.81	111.31	121.52
बिक्री कीमत (पैकड)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	94.93	88.24	107.80
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (खुला)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	468	-1025	96
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पैकड)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	311	-505	-2
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	4180	-8277	480

छ.9. रोजगार

44. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई। आधार वर्ष में 100 की तुलना में जांच अवधि के दौरान सूचीबद्ध रूप में इसमें 73 तक गिरावट आई।

रोजगार		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	73	73

छ.10. मजदूरी

45. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई। जांच अवधि के दौरान यह बढ़कर 36% हो गई। उत्पादन प्रति कर्मचारी/कि.ग्रा. के रूप में परिकलित मजदूरी बढ़कर 32% हो गई।

मजदूरी		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	78.66	97.79	136.28
उत्पादन के प्रति कि.ग्रा. मजदूरी	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	83.78	101.52	151.79

छ.11. उत्पादकता

46. कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घटकर 73 (सूचीबद्ध) हो गई। मजदूरी बढ़कर 36% हो गई, तथापि, इसी अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़कर 42% हो गई।

उत्पादकता		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	कर्मचारी संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	70.45	72.73	72.73
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	133.26	132.45	142.17

छ.12. माल सूची

47. माल सूची की स्थिति में सुधार दिखाई दिया है। सूचीबद्ध रूप में अंतिम स्टॉक में जाँच अवधि के दौरान 17% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। अथशेष स्टॉक में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। अथशेष स्टॉक में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है तथा आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान यह घटकर 75 हो गया। इसी प्रकार से औसत स्टॉक आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घटकर 88 हो गया।

माल सूची		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.64	161.60	117.30
अथशेष स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	46.38	48.53	74.95
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	64.84	84.36	88.37

छ.13. निवेश तथा निवेश पर आय

48. जाँच अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई क्षमता वृद्धि अथवा कोई महत्वपूर्ण नया निवेश नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता में वृद्धि कर रहा है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान आरओसीई में सुधार करने में समर्थ रहा है।

निवेश पर आय	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
निवल परिसंपत्ति (क्लोरोमीथेन)	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	92	101
निवल परिसंपत्तियाँ (मेथिलीन क्लोराइड)	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	81	72
कार्यशील पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	116	100
लगाई गई पूंजी-एनएफए आधार	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	91	80
लगाई गई पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	4257	-9089	601

छ.14. नकद प्रवाह

49. घरेलू उद्योग एक बहुउत्पाद कंपनी है इसलिए उत्पाद के नकद प्रवाह का वास्तविक परिमाण निर्धारित करना संभव नहीं था। तथापि, यह देखा गया है कि कंपनी ने अपने उत्पाद के नकद प्रवाह में क्षति की अवधि में सुधार किया है।

ज. निष्कर्ष

50. क्षति संबंधी कारकों की जांच के आधार पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में सुधार करने में समर्थ रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग आधार वर्ष के दौरान अपनी क्षमता के 100% से अधिक पर प्रचालन कर रहा था तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वह इसे और 3% बढ़ा सका। घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में बिक्री मूल्य की तुलना में जांच अवधि के दौरान 7% की वृद्धि हुई जो इसी अवधि में बेहतर वसूली दर्शाते हुए 26% तक बढ़ी। बाजार माँग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 30% तक वृद्धि हुई। यद्यपि, घरेलू उद्योग इसी अवधि के दौरान उत्पादन को 3% तक बढ़ाने में समर्थ रहा है, तथापि, घरेलू उद्योग को बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घटकर 13% हो गया परन्तु गिरता हुआ हिस्सा क्षति का संकेत नहीं कहा जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के 100% से अधिक का उत्पादन कर रहा है।

झ. अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

झ.1. अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

बाजार हिस्सा		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जाँच अवधि)
आयात में					
विभिन्न देशों से आयात					
सम्बद्ध देशों से आयात	मी. टन	3225.00	8199.00	2697.74	3056.00

यूरोपीय संघ	मी. टन	3224.00	6178.00	2692.00	3012.00
सिंगापुर	मी. टन	1.00	1501.00	5.00	44.00
दक्षिण अफ्रीका	मी. टन	0.00	520.00	0.74	0.00
अन्य देश	मी. टन	630.00	649.00	3258.26	10190.00
कुल आयात	मी. टन	3855.00	8848.00	5956.00	13246.00

51. जांच अवधि के दौरान अनेक देशों से आयात किया गया है। इससे प्रदर्शित होता है कि अन्य देशों से आयात यूरोपीय संघ की तुलना में उच्चतर है। यूएसए, रूस तथा चीन सहित अन्य देशों से आयात आधार वर्ष के दौरान 16% की तुलना में जांच अवधि के दौरान तीव्र रूप से बढ़कर कुल आयातों का 77% हो गया। जहाँ तक यूएसए, रूस तथा चीन का सम्बन्ध है, आयात यूरोपीय संघ के आयातों से कमतर कीमतों पर हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यूएसए, रूस तथा चीन से आयातों का पाटन किया जा रहा है तथा इस संबंध में उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत किया है।

अ.2. मांग में कमी तथा/अथवा खपत के तरीके में परिवर्तन

52. संबद्ध वस्तु की कुल मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 30% तक वृद्धि हुई इसलिए यह कारक ऐसा संभाव्य कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

अ.3. विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा

53. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है तथा घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार लागू नहीं है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से आयातों की भारतीय बाजार में पर्याप्त उपस्थिति है जो कि संबद्ध देशों से आयातों के साथ वास्तविक रूप से बढ़ी है। इसलिए इस कारक को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

अ.4. प्रौद्योगिकी एवं निर्यात निष्पादन का विकास

54. प्रौद्योगिकी अथवा प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के रूप में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं उठाया गया है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग आधार वर्ष के दौरान कम मात्रा का निर्यात कर रहा था तथापि, जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ है। आधार वर्ष में मात्रा के इतने अल्प होने के कारण जांच अवधि के दौरान निर्यातों की समाप्ति को ऐसा कारण नहीं माना जा सकता जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

अ.5. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

55. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार प्रदर्शित हुआ है। यह आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़कर 42% तक हो गयी। कर्मचारियों की मजदूरी जांच अवधि के दौरान 36% तक बढ़ी और प्रति कि.गा. उत्पादन मजदूरी, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़कर 32% तक हो गई।

56. पूर्वोक्त विश्लेषण से यह इंगित होता है कि घरेलू उद्योग पूर्ण क्षमता उपयोग के साथ कार्य कर रहा है तथा साथ ही बिक्री वसूली, लाभप्रदता तथा लगाई गई पूंजी पर आय में सुधार करने में समर्थ रहा है। मांग आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 30% तक बढ़ी। घरेलू उद्योग उत्पादन तथा बिक्री में भी वृद्धि कर सका तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में, घरेलू उद्योग की 100% क्षमता उपयोग की दृष्टि से गिरावट आई।

57. आयातों के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों के हिस्से में गिरावट आई तथा परिणामतः मांग के हिस्से में भी गिरावट आई। दूसरी ओर, अन्य देशों से आयातों के हिस्से में काफी वृद्धि हुई और फलतः मांग के हिस्से में भी तदनुरूप वृद्धि हुई। प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि यूरोपीय संघ से आयात कीमतों की तुलना में अन्य देशों से निर्यात कम कीमतों पर हुए हैं।

58. प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षति नहीं हो रही है जैसाकि आर्थिक मापदण्डों के विश्लेषण में इंगित है। संबद्ध देशों से आयातों की कीमतें, घरेलू उद्योग की कीमतों के मद्देनजर और अन्य देशों से आयातों की कीमतों और वृद्धि के मद्देनजर, घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही हैं।

घ. पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

59. वास्तविक क्षति की जांच के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति के खतरे की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर की गई है।

60. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित जांच करना अपेक्षित है-

क. क्या पाटन जारी रहने के परिणामस्वरूप घरेलू को वास्तविक क्षति होना जारी है;

ख. क्या पाटनरोधी शुल्क को वापिस लिए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

और निम्नलिखित निवेदन किए हैं :-

घ. 1 घरेलू बाजार की संवेदनशीलता

61. इस बात की अत्यधिक संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में निम्नलिखित कारणों से माल की भरमार हो जाएगी:

(क) यूरोस्टैट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को पाठित कीमतों पर निर्यात जारी है और यूरोपीय संघ से अत्यधिक मात्रा आ रही है।

(ख) आयातों और बिक्री कीमत की तुलना से प्रदर्शित होता है कि संबद्ध वस्तु के लिए बाजार अत्यधिक कीमत संवेदनशील है। आयातित उत्पाद की कीमतों में किसी अन्तर से मांग अपेक्षाकृत सस्ते स्रोत के पक्ष में चली जाएगी।

(ग) भारतीय बाजार को मिथाइलीन क्लोराइड के उत्पादन में अग्रणी देशों द्वारा निश्चाना बताया गया है। विभिन्न देशों के सीमाशुल्क विभागों द्वारा जारी आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि निर्यातों की मात्रा के अनुसार उनके सकल निर्यातों में यूरोपीय संघ के संबंध में भारत का प्रथम, चीन और कोरिया के मामले में दूसरा, रूस के मामले में तीसरा और अमरीका के मामले में पांचवा स्थान है। चूंकि भारत इन देशों से निर्यातों का प्रमुख गंतव्य है, अतः यह स्वाभाविक है कि पाटनरोधी शुल्क को किसी भी तरह वापिस लेने के परिणामस्वरूप आयातों की भरमार होगी।

62. प्राधिकारी ने सठाये गए मुद्दे की जांच की और यह नोट किया कि संबद्ध देशों से इतर देशों से आयात अपेक्षाकृत कम कीमतों पर आ रहे हैं जिन पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लग रहा है, अतः पाटनरोधी शुल्क वापिस लिए जाने से संबद्ध वस्तु की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

प्र-2 आयातों का अत्यधिक बाजार हिस्सा

63. संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा पहले ही बहुत अधिक है। यद्यपि प्रमुख मौजूदा आयात शुल्क मुक्त आयात की श्रेणी में हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो भारतीय बाजार के आयातों से पट जाने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

64. प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग का कथन किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तथापि, पाटनरोधी शुल्क वापिस लेने पर शुल्क मुक्त आयातों की पद्धति में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है क्योंकि शुल्क मुक्त सामग्री को निर्यात उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

अ.3 मौजूदा पाटन मार्जिन का स्तर

65. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन बहुत अधिक है, इसलिए शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी। प्राधिकारी पाते हैं कि यूरोपीय संघ के मामले में पाटन मार्जिन नकारात्मक है। सिंगापुर के मामले में पाटन मार्जिन सकारात्मक है तथापि, पाटनरोधी शुल्क वापिस लेने पर आयातों की मात्रा संबद्ध वस्तु की कीमतों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए नगण्य है।

66. प्राधिकारी पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि यूरोपीय संघ और दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर नहीं आ रही हैं। सिंगापुर से आयात नगण्य हैं यद्यपि यह निर्धारित किया गया है कि ये पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों द्वारा पाटन पुनः शुरू किए जाने की संभावना का मूल्यांकन किया है। इस संबंध में प्राधिकारी इस बात को नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से आयात आधार वर्ष की तुलना में लगभग उसी स्तर पर रहे हैं। जांच अवधि के दौरान भी आयातों को अपाटित कीमतों पर पाया गया था। यद्यपि विगत के इतिहास के मद्देनजर पाटन के पुनः शुरू होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, तथापि आयातों की मात्रा एवं कीमत के मद्देनजर इस बात की बहुत कम संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क हटाने के बाद यूरोपीय संघ पाटन करना शुरू कर देगा। दक्षिण अफ्रीका से आयातों के अभाव में और सिंगापुर से आयातों की बहुत कम मात्रा के मद्देनजर इन देशों द्वारा पाटन की पुनरावृत्ति के बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

अ. 4 विदेशी उत्पादकों का निर्यातानुखीकरण

67. संबद्ध देशों में निर्यातकों ने अपनी घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताओं का निर्माण कर लिया है। इन स्रोतों से बहुत अधिक उत्पादन का निर्यात किया जाता है। यूरोपीय संघ के निर्यातक चीन में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे थे जिन पर अब पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है। उत्पादक ने अपने निर्यातों को भारतीय बाजार की ओर मोड़ दिया है। यदि इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क न होता तो भारत को निर्यातों में और अधिक वृद्धि हो जाती। शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में बाजार पाटित माल से भर जाएगा।

68. प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग ने यूरोपीय संघ के निर्यातकों की अतिरिक्त क्षमताओं का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, दूसरे वर्तमान समीक्षा के अंतर्गत यूरोपीय संघ से पाटन मार्जिन को नकारात्मक पाया गया था।

अ. 5 यूरोप में संबद्ध वस्तु की मांग

69. मिथाइलीन क्लोराइड के उत्पादन की आवश्यक रूप से क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन के रूप में परिणति होती है और उत्पादकों का इन दो उत्पादों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मिथाइलीन क्लोराइड की घटती मांग और क्लोरोफॉर्म की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर यूरोप में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तु का जैसी-तैसी कीमतों पर पाटन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूरोपीय संघ के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में लगातार पाटन से यह बात स्पष्ट है। क्लोर अल्काली के अनुसार संबद्ध वस्तु की मुख्य खेप भारत के लिए निर्दिष्ट थी। भारतीय मांग में वृद्धि उनकी जरूरतों के तात्कालिक पूरक के रूप में कार्य कर रही है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि माल के पाटन की स्थिति में उनको या तो कीमतों या मात्रा अथवा संभवतः दोनों में कमी करनी पड़ेगी जिसके फलस्वरूप क्षति संबंधी सभी प्रमुख मापदंडों अर्थात् बिक्री मात्रा, माल सूचियां, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः पाटनरोधी शुल्क को वापिस लेने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

70. प्राधिकारी पाते हैं कि यूरोपीय संघ से आयात पहले ही अन्य देशों से अपेक्षाकृत सस्ते आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं इसलिए शुल्क वापिस लेने से क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।

ट. अंतिम जांच परिणाम

71. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

1. जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं को उनके सामान्य मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्यात हुआ पाया गया है और ये अपाटित हैं। जांच अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका से कोई निर्यात नहीं हुआ है। जांच अवधि के दौरान सिंगापुर से निर्यातों जो बहुत कम मात्रा में हैं, को भारत को उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात हुआ पाया गया है और ये पाटित हैं।
2. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है;

3. और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर से पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।
4. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी दिनांक 14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० 17/1/2001-डीजीएडी द्वारा अनुशंसित और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथा संशोधित) के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत ई यू, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित मिथाइलीन क्लोराइड के सभी आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को हटाने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।
5. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथा संशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

क्रिस्टी एल० फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2005

Final Findings

(Mid-Term Review)

Subject — Anti-Dumping (Mid-Term Review) investigations concerning imports of Methylene Chloride originating in or exported from EU, South Africa and Singapore.

No 15/28/2004- DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof:

A. Background

2(i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified final findings vide Notification No 17/1/2001-DGAD dated 14th August 2003 recommending imposition of anti-dumping duties on all imports of Methylene Chloride originating in or exported from EU, South Africa and Singapore.

ii) The original investigation in this proceeding was initiated on 19th August 2002. The Preliminary findings was issued by the Designated Authority vide Notification No. 17/1/2001-DGAD 24th December, 2002. Final findings of the Authority were issued by the Designated Authority vide Notification No. 17/1/2001-DGAD dated 14th August 2003 and the final duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 49/2003 dated 27th March, 2003.

B. Procedure

3(i) The Customs Tariff Act, 1975(as amended) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 made thereunder require the Authority to review from time to time, the need for the continued imposition of definitive anti dumping duty imposed by the Central Government.

ii) The Designated Authority, received an application from the European Commission on the behalf of exporters including Ineos Chlor, of European Union for review of the antidumping duties levied on the subject goods, on the grounds of changed circumstances. On the basis of positive information submitted by the above-mentioned applicants the Designated Authority considered that mid-term review of the anti dumping duty in force would be appropriate in view of the changed circumstances brought to the notice to the Authority. Accordingly, a public notice dated 28th January, 2005, was issued and published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping mid term review investigation under Rule 23 of the Antidumping Rules read with Article 11.2 of the Agreement on Antidumping, in respect of the duty in force against the subject countries as above, to determine whether the continued imposition of the duty is required to offset dumping, and whether injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

iii) Having decided to review these final findings, the Authority initiated the present investigations vide Notification No. 15/28/2004-DGAD dt.28/1/2005 to review the need for continued imposition of anti dumping duty on Methylene Chloride from EU, South Africa and Singapore. (hereinafter referred to as subject countries) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975(as amended) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995(hereinafter referred to as AD Rules). This review covers all aspects of Notification No. 17/1/2001-DGAD dated 14th August 2003.

iv) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, alongwith the initiation notification, to the known exporters/producers, as per addresses available in the original investigation, in the subject countries in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information.

v) Notices were also sent to the domestic industry in India seeking relevant information in accordance with the Rules;

vi) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.

vii) Questionnaires were sent to the known importers and consumers of subject goods in India, as per addresses available in the original investigation, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4),

viii) Investigations were carried out for the period of investigation (POI) from 1st April 2003 to 31st March 2004 (12 months). However injury analysis have been carried out for the years April 2000 – March 2001, April 2001 – March 2002, April 2002 – March 2003 and the period of investigation.

- ix) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;
- x) Copies of the initiation notification were also sent to FICCI, CII and ASSOCHAM for wider circulation.
- xi) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.
- xii) M/s. Gujarat Alkali & Chemicals Ltd., the domestic producer of the subject goods and the original petitioner in the original investigation submitted its responses opposing the review;
- xiii) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP);
- xiv) The Authority held a public hearing on 16/6/05 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, the applicant exporters of the subject goods from the European Union and other interested parties. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;
- xv) The views expressed by various interested parties in response to the initiation notification and subsequent to the public hearing are discussed in the relevant paragraphs to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in relevant paragraphs.
- xvi) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed on 13.9.2005 to known interested parties and comments received have been duly considered in the findings.

**** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product involved in the original investigation and the current review is Methylene Chloride falling under heading No. 29031200 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present

investigation. This being a changed circumstances mid-term review investigation, the investigation covers the product covered in the original investigation. No argument has been extended, by any interested party, on the issue of product under consideration or like article and therefore, the Authority holds that the product being manufactured by the domestic industry and the product being manufactured and exported from the subject countries are like articles as per AD Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY

5. In the original investigation the application for anti-dumping investigation was filed by M/s. Gujarat Alkali & Chemicals Ltd., on behalf of the domestic industry. The applicant was the major producer of the subject goods in India and had the required standing to file the petition under AD Rules. In this mid-term review M/s. Gujarat Alkali & Chemicals Ltd. is providing all relevant information and supported by M/s Chemplast Sanmar and M/s SRF Ltd. M/s Chemplast Sanmar Ltd. also submitted costing and injury information. However, on verification the information was found to be incorrect and unreliable, hence, the costing and injury information provided by the company have not been relied upon in this investigation. M/s Gujarat Alkali & Chemicals Ltd. therefore, constitute domestic industry within the meaning of AD Rules.

E. INITIATION OF THE REVIEW AND ARGUMENTS RAISED

E1. VIEWS OF APPLICANTS

6. Views of the applicant is summarized below

The applicant claims that the condition of injury to the domestic industry has changed substantially requiring a review of the anti dumping measure in force. It is claimed that in the financial year 2002-03, the production of Methylene Chloride by Gujarat Alkalies and Chemicals Limited was 25481 MT. The applicant claims that though the production has increased only by 1 % from 2002-03 to 2003-04 but sales have increased by 14 % from Rs. 616 million to Rs. 702 million in the same period. The applicant further claims that the installed capacity for Methylene Chloride had since 2002 remained at 23760 MT and utilization has been more than 100 % as production levels had reached 25481 MT in 2002-03 and 25784 in 2003-04, therefore, the domestic industry is producing at its maximum and is not suffering under utilization of the capacity. The applicant has also claimed that the demand for Methylene Chloride in India is approximately 57000 MT/ annum, however, current annual production levels in India for the domestic manufacturers (Gujarat Alkalies Ltd., Chemplast Sanmar and SRF Ltd.) lie at approximately 30000 MT. In order to meet the domestic demand, the user industry in India is obliged to import Methylene Chloride, in spite of the Anti-dumping duty currently in force. The domestic producers have not increased their capacity in spite of growing domestic consumption, which suggests that there are elements other than alleged dumping which are impeding the domestic industry from expanding their production. The applicant also stated that prices on the market have

doubled since the period of investigation. At the time of imposition, prices were in the range of US \$ 270-350/MT, these prices have now increase to US \$ 650/MT and have remained at this level for a considerable period of time. The applicant claims that these high prices would indicate that the domestic industry is not suffering any injury on account of dumping. It has been informed that the average export price to India for Methylene Chloride during 2004 was \$ 655/MT for packed product and \$ 611/ MT for bulk product.

E2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

7. Views of the Domestic industry are summarized below

- i) The applicant is not clear about the product under consideration whose review is being sought. The covering letter, which is a letter from the European Commission, states about Methylene Chloride as the product under consideration under the heading subject, while the letter refers to review of the duty on imports of Choline Chloride.
- ii) The application is vague about the applicant who has sought the review of anti-dumping duties.
- iii) The Designated Authority should be satisfied on the basis of positive information submitted by the applicant that there is no need to review Anti-dumping Duties in force. Such satisfaction of the Designated Authority must be before initiation and not during the course of investigation. In the instant case, no positive information has been provided by the applicant justifying the need for review of the Anti-dumping Duty.
- iv) The applicant M/s Ineos Chlor neither cooperated during the original investigation nor during present investigation. Even during the public hearing M/s Ineos Chlor did not make any submission.
- v) A review can be taken up at the request of an interested party provided the circumstances in which Anti-dumping Duty was recommended earlier have changed and the duty is required to be revoked, increased or reduced. However, in the instant case the alleged circumstances do not constitute 'changed circumstances' warranting mid-term review. The application filed by European Commission or a European producer lacks positive evidence demonstrating changed circumstances. It is not the ground of the applicant that the product is no longer being dumped in the Indian market. Imports from European Union and Singapore have continued at dumped prices even after imposition of duty.
- vi) The claim of applicant is restricted only to 'no material injury' and does not extend to 'no likelihood of recurrence of injury to the Domestic Industry'. Therefore, claim is insufficient in the light of legal requirements for initiation of review or discontinuation of the Anti-dumping Duty.
- vii) The claim of applicant is not based on Methylene Chloride, the production under consideration in the present case and the applicant has relied on irrelevant and useless information.
- viii) Marginal improvement in production, sales and capacity utilization is a direct consequence of continuous efforts of the Indian producers to improve

- the production. By no stretch of imagination this can be considered as reasonable ground for revocation of anti-dumping duty.
- ix) Inability of the domestic industry to meet the demand was not a pre-requisite for imposition of anti-dumping duty. It cannot now become a parameter for revocation of the anti-dumping duty.
 - x) The applicant has argued that export prices have increased since the imposition of duties. However, it should be seen that world over prices of raw material have increased. Prices of Chlorine which is the major raw material has increased significantly after imposition of the Anti-dumping Duty and the increase in export prices as stated by the exporter is due to increase in cost of production.
 - xi) There is no application on the record by any producer/exporter from Singapore and South Africa or any importer in India for reviewing Anti-dumping Duty on imports from Singapore and South Africa.
 - xii) It is a settled principle of law that one who asserts has to prove his assertion. Therefore, the onus of establishing that there is a need for withdrawal of anti-dumping duty in force lies on the party which is seeking the said withdrawal.

E3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

8. The authority has taken note of arguments raised by the domestic industry and is of the view that European Commission has made request on behalf of the exporters including M/s Ineos Chlor of the European Union. The request was sent through diplomatic channel to the Designated Authority. As per Anti-dumping Agreement and Anti-dumping Rules, European Commission and exporter M/s Ineos Chlor both are interested parties in this case and have right to file the application. In this case European Commission being interested party has right to file the application for review on behalf of the exporter.

9. The argument raised by the domestic industry that the product is not clear as in the body of the forwarding letter 'Choline Chloride' is mentioned. The Authority is of the view that the product under consideration is Methylene Chloride as is very clearly stated on the letter under the heading subject. The letter is accompanied by a write up giving details about changed circumstances relating to Methylene Chloride. On the letter Choline Chloride is also mentioned, however, it cannot negate a complete write up on changed circumstances relating to Methylene Chloride.

10. The lack of cooperation by the exporter or any other interested party is visualized under Article 6.8 of the Anti-dumping Agreement and Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. The Authority follows the rules already in operation in this regard.

11. The domestic industry has argued that the 'satisfaction' of the Authority must be before the initiation and not during the course of the investigation. In this regard they have drawn the attention of the Designated Authority to Article 11(2) of the Anti-dumping Agreement.

12. The Authority has taken note of the provisions of Article 11(2) of the Anti-dumping Agreement and Section 9(5) of the Customs Tariff Act and relevant Anti-dumping Rules. Section 9A (5) read with Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall from time to time review the need for continued imposition of anti dumping duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal. And also Article 11.2 of the Agreement provides that the Authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

13. The Authority has examined the argument and is of the view that the condition 'satisfaction' in Rule 23 refers to the satisfaction of the Authority of the need of continued imposition of duty after conducting a proper investigation and not for initiation of the review. What is required for initiating a review is positive information with the Authority on which the Authority can rely upon to decide whether a review is required to examine the need for continued imposition of the duty. In the instant case the applicant had filed positive information before the Authority in its review application and the review was initiated based on these positive information filed. The positive information imply any information on basis of which the Authority can reasonably act. However, it cannot be expected from the Authority to test the information with strict evidence at the initial stage as is done during the course of the investigation. Production of evidence to substantiate the claims and counter claims by various parties are the matter of investigation and are to be submitted by the parties including the party making a request for review during the course of investigation. The outcome of the review will however, depend upon the quality of evidence submitted by various parties to the review. Therefore, the Authority is of the view that the review has been correctly initiated on the basis of positive information available with the Authority which suggested that a review of the duty in force was warranted.

14. The domestic industry contended that the onus of establishing the need for withdrawal of anti-dumping duty at this pre-mature stage is on the petitioner. The domestic industry is not required to establish the need for continued imposition of anti-dumping duty and the domestic industry is not required to establish that the revocation of anti-dumping duty would result in recurrence of injury and anti-dumping duty is required to be continued. The Authority has examined the issue and taken note of provision contained in Article 11 (1) & 11(2) and Section 23 of the Anti-dumping Rules. As per these provisions, the Authority, on being satisfied on the basis of information received that there is no justification for the continued imposition of anti-dumping duty, the Authority shall recommend for withdrawal of such duty. The

Authority finds that this provision put onus on the Authority to have satisfaction on the basis of information received by it. The Authority is also required to examine material for its satisfaction whether continued imposition of Anti-dumping duty will help in preventing recurrence of injury to the domestic industry. This also imply lack of information for continued imposition of anti-dumping duty. Any interested party cannot take shelter on the ground that the other interested party is not cooperating, therefore, adverse view should be taken. Neither the Anti-dumping Agreement nor Anti dumping Rules gives mandate to take such adverse view against the non-cooperating parties. To deal with the non-cooperating interested parties the Authority is required to rely on facts available as per provision of the Agreement and the Rules. Therefore, the Authority is relying on the information available to it from any source, including information provided by the interested parties.

15. The Authority also takes note of other arguments raised by the domestic industry regarding applicant's claim about lack of injury to the domestic industry. These arguments have been taken into account while analyzing the injury to the domestic industry.

F. METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DUMPING MARGIN:

DUMPING DETERMINATION: NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F1. THE EUROPEAN UNION

F1.1. NORMAL VALUE

16. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975. None of the exporters / producers from EU has filed submissions for the determination of normal value in the form and manner required by the Authority.

17. Article 6.8 of the Agreement provide that in case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Annex II to the Agreement further provides that such determination can even be made on the basis of information provided by the domestic industry. Since none of the exporters / producers from EU has filed the required information for determination of normal value, the normal value for all exporters / producers has been constructed based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules. The normal value is therefore, constructed as US\$ ***/MT for loose material and US\$ ***/MT for packed material. for all exporters / producers from EU.

F1.2. EXPORT PRICE

18. The export price is determined on the basis of import statistics provided by DGCI&S. As per DGCI&S import statistics EU has exported 3012 MT of during the POI. After segregating data for loose and packed material the adjustments on account of in land freight, ocean freight and marine insurance have been adjusted to arrive at ex-factory export prices. The ex-factory export price for loose material is determined as US\$ ***/MT and US\$ ***/MT for packed material for all exporters/producers from EU.

F2. SINGAPORE**F2.1. NORMAL VALUE**

19. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975. None of the exporters / producers from Singapore has filed submissions in the form and manner required by the Authority. Article 6.8 of the Agreement provides that in cases any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Annex II to the Agreement further provides that such determination can even be made on the basis of information provided by the domestic industry. Since none of the exporters / producers from Singapore has filed the submissions for determination of normal value, the normal value for all exporters / producers has been constructed based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules. In absence of any other information, the information provided by the domestic industry has been considered as the basis of normal value for the purpose of assessment of extent of current dumping. The normal value is therefore, constructed as US\$ ***/MT for all exporters / producers from Singapore.

F2.2. EXPORT PRICE

20. The export price is determined on the basis of import statistics provided by DGCI&S. As per DGCI&S import statistics Singapore has exported 44 MT of Methylene Chloride during the POI. To arrive at ex-factory export price, adjustments on account of inland freight, ocean freight and marine insurance have been considered as provided by the domestic industry. The ex-factory export price is determined as US\$***MT for all exporters / producers from Singapore.

F3. SOUTH AFRICA

21. As per DGCI&S import statistics South Africa has not made any export of Methylene Chloride during the POI. Therefore, the Authority could not calculate export price.

F4. DUMPING MARGIN

22. Based on the normal value and export price as determined above, the Authority determined the dumping margin as under:

SUBJECT COUNTRIES	NORMAL VALUE(\$/MT)		EXPORT PRICE(\$/MT)		DUMPING MARGIN (%)	
	(Loose)	(Packed)	(Loose)	(Packed)	(Loose)	(Packed)
EU	***	***	***	***	-5	-9
Singapore		***		***		83

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

G1. INJURY DETERMINATION AND CONTINUATION OF INJURY

G1.1. VIEWS OF THE APPLICANTS

23. The applicant has submitted that the domestic industry has improved its performance and does not suffer any material injury. The applicant claims that though the production has increased only by 1 % from 2002-03 to 2003-04 but sales have increased by 14 % from Rs. 616 million to Rs. 702 million in the same period. The applicant further claims that the installed capacity for Methylene Chloride had since 2002 remained at 23760 MT and utilization has been more than 100 % as production levels had reached 25481 MT in 2002-03 and 25784 in 2003-04, therefore, the domestic industry is producing at its maximum and is not suffering under utilization of the capacity. At the time of imposition, prices were in the range of US \$ 270-350/MT, these prices have now increase to US \$ 650/MT and have remained at this level for a considerable period of time. The applicant claims that these high prices would indicate that the domestic industry is not suffering any injury on account of dumping. It has been informed that the average export price to India for Methylene Chloride during 2004 was \$ 655/MT for packed product and \$ 611/ MT for bulk product.

G1.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

24. Views of Domestic industry are summarized below:

Domestic industry has been making dedicated efforts to optimize its production. Imposition of anti dumping duty helped the domestic industry tremendously in improving its production volumes. It has been argued by the petitioner that the domestic industry has not enhanced capacity. While capacity addition in this product are not feasible in the short run, the domestic industry has made significant increase in production volumes, once it has been protected from unfairly priced dumped imports. As a result, production and capacity utilization of the domestic industry has not declined and has rather shown improvement. The improvement in the performance of profits, cash flow and return on investments is due to imposition of anti dumping duty on dumped imports. This clearly shows that the performance of the domestic industry was adverse in terms of these parameters only because of dumping of the product in the market

25. Changes in the employment level with the domestic industry are more a result of overall situation of the domestic industry and is not reflective of performance of the product per-se. Employment with the domestic industry has declined more as an overall corporate performance of the domestic industry. The wages with the domestic industry increased because of annual wage increments the domestic industry must offer to its employees. Productivity of the domestic industry has improved with the imposition of anti dumping duty. While the domestic industry has been able to reduce employment on the one hand, it has been able to increase its production level on the other hand

G1.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

26. The Authority proposes to analyse the injury parameters to determine whether the domestic industry is continuing to suffer material injury on account of such dumped imports.

G2. VOLUME OF IMPORT AND IMPORT PRICES

27. DGCI&S data for the injury analysis period shows that imports have taken place from several sources including the subject countries during the injury investigation period. Accordingly, the import as reported by DGCI&S are as follows:

Imports from various countries		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Imports From Subject Country	MT	3225.00	8199.00	2697.74	3056.00
European Union	MT	3224.00	6178.00	2692.00	3012.00
Singapore	MT	1.00	1501.00	5.00	44.00
South Africa	MT	0.00	520.00	0.74	0.00
Other Countries	MT	630.00	649.00	3258.26	10190.00
Total Imports	MT	3855.00	8848.00	5956.00	13246.00
Market share in Imports					
Subject Countries	%	83.66	92.67	45.29	23.07
European Union	%	83.63	69.82	45.20	22.74
Singapore	%	0.03	16.96	0.08	0.33
South Africa	%	0.00	5.88	0.01	0.00
Other Countries	%	16.34	7.33	54.71	76.93

28. Imports as per the transaction-wise DGCI&S data shows imports of 3012 MT from subject countries during POI. The domestic industry have contended that volume of imports as per data published by Eurostat establishes much higher import at 10200 MT during January-December 2004. The viewpoint of domestic industry is that import of subject goods are either not being reported to DGCI&S or have been cleared under some other Customs classification with the possibility of circumvention of Anti-dumping Duty.

29. The Authority has taken note of fact that Eurostat data shows much higher exports to India from European Union, however, it has also been taken note that data relate to calendar year from January to December whereas POI is for the financial year i.e. April 03 to March 04.

30. The data published by IBIS also shows similar quantity of imports in India as reported by DGCI&S. Value-wise also data published by IBIS shows similarities to that of DGCI&S. Though there is a small difference over the per unit value of the products, it is the volume which shows significant difference in data published by DGCI&S, IBIS and Eurostat. The Authority, therefore, has taken note of the fact that import quantity could be higher than what has been reported by DGCI&S.

31. The data reported by DGCI&S and IBIS does not make any difference between loose and packed imports, therefore, for segregating data of imports the Authority has agreed to method adopted by domestic industry. By this method, the data of only Kandla and Mumbai Ports have been used, as only these two ports have facility to handle loose imports. Further, only higher volume of imports have been taken into loose category as loose product is not generally imported in small quantity.

32. The data shows that the share of subject countries in total imports shows declining trend as it declined to approximately 23% during POI as compared to approximately 84% during the base year. From the South Africa, import is nil during

POI. From Singapore, imports constitute 0.33% during POI whereas from European Union, imports constitute approximately 23% during POI. Imports data also shows significant rise of imports from other countries. It grown to 77% during POI as compared to 16% during the base year.

33. In post-disclosure submissions the domestic industry has contended that the data from the Kandla Port should have been used to calculate the export price. In this regard, the Authority observed that the domestic industry in its original submission used data from IBIS to calculate export prices. In subsequent submissions they used data provided by DGCI&S and segregated imports transactions made at Kandla and Bombay ports and calculated the export prices, however, while calculating the export price certain high volume transactions were considered under packed material. The Authority has used same data as segregated by domestic industry, however, high volume transactions were considered as loose material and export prices were calculated accordingly. The contention of the domestic industry that data of only Kandla port should have been used to calculate the export price is untenable as Kandla and Bombay ports both have facility to handle loose material, therefore, imports data from both the ports have been used to calculate the export prices.

G3. CAPACITY, OUTPUT AND CAPACITY UTILIZATION OF DOMESTIC INDUSTRY

34. The performance of the domestic industry has also been examined with reference to its capacity, output and capacity utilization and impact of the dumped imports on these parameters, if any. There is no change in capacity of domestic industry. It remained the same during POI as compared to base year 2000-01. Though the capacity has not changed during POI yet it shows improvement in utilization of capacity. It had been working at more than 100% of the capacity even in the base year yet it shows further growth of 3% during POI as compared to base year. Similarly, production shows growth of 3% during POI as compared to the base year.

Utilization of Capacity		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	100.00	100.00	100.00
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	93.89	96.33	103.40
Output					
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	93.89	96.33	103.40

G4. DEMAND AND MARKET SHARES

35. The total demand has been estimated based on the combined volume of domestic sales and imports from other countries, as well as imports made into the domestic market from the Subject countries. Demand shows growth of 38% during POI as compared to base year. Market share in demand shows significant decline to 69

during POI from the base year in respect of the subject countries. However, for the other countries it shows robust growth to 1171 from base of 100 in 2000-01. Market share of the domestic industry shows declining trend and it declined to 78 during POI from the base year. Similarly share of other domestic producers declined to 83 during POI as compared to base year. It shows that in growing market though domestic industry was in position to improve capacity utilization and could also improve sales in value and volume term yet market share of domestic industry and other Indian producers declined. Market share from the subject country also shows declining trend, however, countries other than subject countries gained significant share and grown to 1171 during POI from the base of 100 in 2000-01.

In Demand		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Merchant Demand	MT	***	***	***	***
		100.00	115.81	108.83	138.14
Imports from subject countries	MT	3225.00	8199.00	2697.74	3056.00
Trend	Indexed	100.00	254.23	83.65	94.76
Imports from other countries	MT	630.00	649.00	3258.26	10190.00
Trend	Indexed	100.00	103.02	517.18	1617.46
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	93.73	96.31	107.12
Sales of other Indian producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	104.82	106.06	114.31
Market share in Demand					
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	80.93	88.49	77.55
Other Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	90.51	97.45	82.75
Subject Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	219.53	76.86	68.60
Other countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	88.95	475.21	1170.88
Total		100.00	100.00	100.00	100.00

G5. SALES REALISATION OF THE DOMESTIC INDUSTRY

36. Sales volume have grown by 7% during POI as compared to base of 100 in 2000-01. Sales value has grown by 23% in the same time showing better realization.

37. Sales volume of loose material have grown by 1% during POI, however, sales value increased by 22% during the same period showing significant improvement in realization. Sales volume of packed material have grown by 26% during POI as compared to base year however, sales value increased by 36% during the same period showing better realization.

Particulars	Unit	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04 (POI)	
		Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value
Actual & Potential Decline in			Rs/Lacs		Rs/Lacs		Rs/Lacs		Rs/Lacs
Sales									
Sales (Domestic)	MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	94	86	96	101	107	126
Sales loose	MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	90	80	91	101	101	122
Sales Packed	MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	106	100	112	99	126	136
Export Sales	MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	33	31	1	2	0	0

G6. PRICE UNDERCUTTING

38. A comparison for subject goods during the period under investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. The landed value of imports from the subject countries was lower than the net sales realization of the domestic industry for the subject goods during the POI thereby, undercutting the selling price of the domestic industry. The undercutting margin was in the range as mentioned below during the POI.

Price Undercutting	EU(loose)	EU(Packed)	Singapore (Packed)
Net sales realization	***	***	***
Landed Value	***	***	***
Price Undercutting	***	***	***
Price Undercutting (%)	***	***	***
Price Undercutting range	1-10%	1-7%	20-30%

G7. PRICE UNDERSELLING

39. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. Also in order to eliminate inefficiencies, the capacity utilization has been normated. The analysis shows that the weighted average landed value of the subject goods from subject countries is less than the non injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margin was in the range as mentioned below during the POI.

Price Underselling	EU(loose)	EU(Packed)	Singapore (Packed)
Non Injurious Price	***	***	***
Landed Value	***	***	***
Price Underselling	***	***	***
Price Underselling (%)	***	***	***
Price Underselling range	5-15%	4-13%	25-35%

40. Further, the landed value of subject goods is lower than the domestic selling price of the domestic industry thereby, undercutting the domestic sales prices.

OTHER INJURY PARAMETERS

41. After having examined the major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed here as follows:

G8. PROFITABILITY

42. The profitability of the domestic industry has been analysed from the record of the company:

43. The cost of production excluding interest increased by 17% in case of loose product and 15% for the packed product during POI as compared to the base year. Selling price shows increase of 22% for the loose product and 8% for the packed product. Profitability has shown improvements and in indexed form for loose product loss of 100 in the base year which turned positive and in the indexed form it has become 96. For the packed product it shows deterioration and profit of 100 in the base year has turned negative during POI to -2. Profit shows improvement and it increased to 480 during the POI as compared to 100 of the base year.

Profits- Domestic Sales		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Cost of Production (loose)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	82.89	125.00	109.28
Net Cost of Production excluding interest (loose)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	130	117
Cost of Production (packed)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	122	102
Net cost of production excluding interest (packed)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	125	115
Selling Price (loose)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	88.81	111.31	121.52
Selling Price(packed)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	94.93	88.24	107.80

Profit Before Interest & Taxes (loose)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	468	-1025	96
Profit before Interest & Taxes (Packed)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	311	-505	-2
Profit before Interest & Taxes	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	4180	-8277	480

G9. EMPLOYMENT

44. Number of employees have been reduced during POI as compared to base year. In indexed form it declined to 73 during POI as compared to 100 of base year

Employment		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	70	73	73

G10. WAGES

45. Wages have increased during POI as compared to base year. It increased by 36% during POI. Wages calculated as per/kg. of production grown by 32%.

Wages		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Wages paid to employees	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	78.66	97.79	136.28
Wages Per KG of Production	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	83.78	101.52	131.79

G11. PRODUCTIVITY

46. The number of employees has been reduced to 73 (Indexed) during POI as compared to base year. The wages have increased by 36%, however, the productivity per employee improved by 42% during the same period.

Productivity		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Productivity per Employees					
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	70.45	72.73	72.73
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	133.26	132.45	142.17

G12. INVENTORIES

47. The position of inventory has shown improvement. In the indexed form the closing stock shows increase of 17% during POI. The opening stock shows declining trend and it declined to 75 during POI as compared to base year. Similarly the average stock declined to 88 during POI as compared to base year

Inventories			2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Closing Stocks	MT		***	***	***	***
Trend	Indexed		100.00	104.64	161.60	117.30
Opening stocks	MT		***	***	***	***
Trend	Indexed		100.00	46.38	48.53	74.95
Average Stocks	MT		***	***	***	***
Trend	Indexed		100.00	64.84	84.36	88.37

G13. INVESTMENT AND RETURN ON INVESTMENT

48. There has been no capacity addition or any remarkable fresh investment by the applicants during the investigation period. The domestic industry has been improving its profitability. The domestic industry has been able to improve ROCE during the POI from the base year.

Return on Investment	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Net Assets (Chloromethane)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	92	101
Net Assets (Methylene Chloride)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	81	72
Working Capital	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	116	100
Capital Employed-NFA Basis	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	91	80
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	4257	-9089	601

G14. CASHFLOW

49. The domestic industry is a multi-product company therefore it was not possible to determine the actual magnitude of cash-flow of the product. However it has been observed that the company has improved its cash-profit of the product over the period of injury.

H. CONCLUSION

50. On the basis of examination of injury factors, it is noted that the domestic industry have been able to improve production and capacity utilization of the subject goods. Though the domestic industry was working at more than 100% of its capacity during the base year, yet it could improve it further by 3% during POI as compared to

the base year. Sales volume of the domestic industry improved by 7% during POI as compared to the sales value which grown by 26% during the same period showing better realization. The market demand has grown by 30% during POI as compared to base year. Though the domestic industry have been able to increase production by 3% during the same period, however, market share of the domestic industry declined by 18% during POI as compared to base year, but declining share cannot be sign of injury as domestic industry is producing at more then 100% of its capacity.

I. OTHERS KNOWN FACTORS AND CAUSAL LINK

I.1. Volume and prices of imports from other sources

Market share		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
In imports					
Imports from various countries					
Imports From Subject Country	MT	3225.00	8199.00	2697.74	3056.00
European Union	MT	3224.00	6178.00	2692.00	3012.00
Singapore	MT	1.00	1501.00	5.00	44.00
South Africa	MT	0.00	520.00	0.74	0.00
Other Countries	MT	630.00	649.00	3258.26	10190.00
Total Imports	MT	3855.00	8848.00	5956.00	13246.00

51. During the POI, imports have taken place from many countries. It shows that imports from the other countries are higher as compared to European Union. The imports from other countries including USA, Russia and China have risen sharply to 77% of total imports during POI as compared to 16% during the base year. As regards USA, Russia and China, the imports are on lower prices than that from the European Union. The domestic industry has contended that the imports are also being dumped from USA, Russia and China.

I.2. Contraction in demand and./ or change in pattern of consumption

52. The total demand of the subject goods shows significant growth. It increased by 30% during POI as compared to the base year, therefore, this factor is not possible reason which could have caused injury to the domestic industry.

I.3. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

53. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. Moreover, imports from other sources have sizable presence in the Indian market, which has grown substantially along with the imports

from subject countries. Therefore, this factor could not have been reason to cause injury to the domestic industry

I.4. Development of technology and export performance

54. Technology or technology related issues have not been raised by any interested party as cause of injury to the domestic industry. It is noted that the domestic industry was exporting small quantity during the base year however, but now there is no export during the POI. The quantity being so small in the base year, so cessation of exports during the POI cannot be reason which could have caused injury to the domestic industry.

I.5. Productivity of the Domestic Industry

55. Productivity of the domestic industry has shown improvement. It has improved by 42% during POI as compared to the base year. Wages to the employees have increased by 36% during POI and wages per kg. of production also increased by 32% during POI as compared to the base year.

56. The foregoing analysis indicates that the domestic industry is working at full capacity utilization and also have been able to improve sales realization, profitability and return on capital employed. The demand had grown by 30% during POI as compared to base year. The domestic industry could also improve production and sales, however, market share of domestic industry declined in view of 100% capacity utilization of the domestic industry.

57. As per data of imports, the share of subject countries had declined in imports and consequently share in demand has also declined. On the other hand, share in imports from other countries had increased significantly and consequently share in demand also increased accordingly. The Authority also finds that exports from other countries are at low prices than the import prices from European Union.

58. The Authority finds that domestic industry is not suffering injury as indicated by analysis of economic parameters. The prices of imports from subject countries are not causing impact on prices of domestic industry in view of prices of domestic industry and in view of prices and rise in imports from other countries.

J. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

59. In addition to the examination of material injury, likelihood of recurrence of injury or threat of injury to the domestic industry has been examined by the Authority on the basis of the claims made by the domestic industry.

60. The domestic industry has submitted that the Designated Authority is required to examine -

- a. Whether the domestic industry is continuing to suffer material injury as a result of continued dumping;
- b. Whether the domestic industry is likely to suffer injury as a result of revocation of anti-dumping duty.

And made under mentioned submissions:-

J.1 . Vulnerability of the domestic market

61. There is a great possibility that this continuance of anti-dumping duty will result in flooding of material in Indian market because of the following reasons:

a) The product is continued to be exported to India at dumped prices from subject countries and also huge volume is coming European Union as per data published by Eurostat.

b) Comparison of imports and sales price shows that the market for the subject goods is highly price sensitive. Any difference in prices of the imported product would drag the demand in favour of cheaper source. In such case domestic industry would have to either reduce the prices or the market would be flooded with imports from subject countries.

c) The Indian market is targeted by countries which are leaders in the production of Methylene Chloride. Data released by Customs Departments of various countries shows that as per quantum of exports, rank of India in their total exports is a first in respect of European Union, second in case of China and Korea, third in case of Russia and fifth in case of USA. Since India is a prime destination of exports from these countries, it is thus natural that any revocation of anti-dumping duty would result in flooding of imports.

62. The Authority examined the issue raised and noted that imports from countries other than subject countries are at cheaper prices which are not attracting any anti-dumping duty, therefore revocation of anti-dumping duty would unlikely to affect the price of the subject goods adversely.

J.2. Significant market share of imports

63. Market share of subject countries is already significant. While major present imports are in the category of duty free import which are not subject to anti-dumping duty. In case anti-dumping duty is revoked, imports are likely to flood the Indian market which would lead to recurrence of injury to domestic market.

64. The Authority finds that assertion of domestic industry is not backed by any evidence, however, it is unlikely that pattern of duty free imports would change on revocation of anti-dumping duty as duty free material is required to be used for export production.

J.3. Level of current dumping margin

65. Domestic industry has contended that dumping margin from subject countries are very high, therefore, withdrawal of duty would lead to recurrence of injury to the

domestic industry. The Authority finds that dumping margin is negative in case of European Union. The dumping margin is positive in case of Singapore however, the volume of imports is insignificant to make any significant impact on prices of the subject goods on revocation of anti-dumping duty.

66. The Authority has already determined that the subject goods are not entering in to the Indian market at dumped prices from the European Union and South Africa. The volume of imports from Singapore is insignificant (merely 0.33% of total imports), though it has been determined to be entering at the dumped prices. The Authority has evaluated the likelihood of resumption of dumping by the subject countries. In this regard, the Authority takes note of the fact that imports from European Union remain approximately at the same level during POI as compared to the base year despite the anti-dumping duty. The imports during POI also found to be at un-dumped prices. Though the resumption of dumping cannot be ruled out in view of the past history, however, in view of the volume and price of imports, there is little possibility that the European Union would commence dumping after withdrawal of anti-dumping duty. In view of the absence of imports from South Africa and insignificant volume of imports from Singapore, it can be safely concluded that there is no likelihood of recurrence of dumping by these countries in case the anti-dumping duties are revoked.

J.4. Export orientation of foreign producers

67. Exporters in the subject countries have built capacities far in excess of their domestic demand. Significant production is exported from these sources. Exporters in European Union were dumping the subject goods in China, which are now attracting anti-dumping duty. The producer shifted their exports to the Indian market. Exports to India would have increased further but for anti-dumping duty in force at present. In case of discontinuation of duty the market would be flooded with the dumped material.

68. The Authority finds that domestic industry has not submitted any evidence of excess capacities of the exporters from European Union, secondly, under the present review, dumping margin from the European Union found to be negative.

J.5. Demand of the subject goods in Europe

69. The production of Methylene Chloride necessarily results in production of Chloroform and Carbon Tetrachloride and producers have no control on these two products. In view of the declining demand of the Methylene Chloride and increasing demand of Chloroform, the producers in Europe have no option but to dump the subject goods at whatever prices. This is evident from continued dumping by exporters from European Union in the Indian market. As per Chlor Alkali, the major shipment of subject goods were destined to India. Increase in Indian demand is acting as an instant filler to their needs. The domestic industry has also contended that in the event of dumping of the material, they would either have to reduce the prices of volume or possibly both which in turn would adversely impact all major injury parameters viz. sales volume, inventories, production, capacity utilization, profits, cash flow and return

on investment. Thus, revocation of anti-dumping duty would result in recurrence of injury to the domestic industry.

70. The Authority finds that imports from European Union is already competing with cheaper imports from other countries, therefore, withdrawal of duty is unlikely to result in recurrence of injury.

K. FINAL FINDINGS

71. The Authority after considering the foregoing concludes that:

- (1) Subject goods originating in or exported from European Union during POI are found to be exported at above their normal value and are undumped. No imports have taken place from South Africa during the period of investigation. Volume of exports from Singapore during POI, which is insignificant (merely 0.33% of total imports), has been found to be exported to India below their normal value and are dumped;
- (2) The domestic industry has not suffered material injury due to imports from subject countries;
- (3) And discontinuation of anti-dumping duties on the subject goods from subject countries is not likely to lead to the recurrence of dumping or injury to the domestic industry;
- (4) In view of the above, the Designated Authority considers it appropriate to recommend discontinuation of the anti-dumping duties recommended earlier vide Notification No17/1/2001-DGAD dated 14th August 2003 and imposed on all imports of Methylene Chloride classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (as amended) originating in or exported from EU, South Africa and Singapore.
- (5) An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (as amended).

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority